>

Title : Further discussion on the motion for consideration of the Representation of the People (Amendment) Bill, 2009, as passed by Rajya Sabha moved by Dr. M. Veerappa Moily on 2 December, 2009.

MADAM SPEAKER: The House shall now take up further consideration of the Representation of the People (Amendment) Bill, 2009. Shri J.P. Agarwal to continue his speech.

श्री जय प्रकाश अग्रवाल (उत्तर पूर्व दिल्ली): अध्यक्ष महोदया, मुझे बहुत खुशी है कि मैंने जो बातें उस दिन रखीं, उस दिन समय कम था तो मैं अपनी बात पूरी नहीं कर पाया। मैंने एक बात बहुत साफ तौर पर कही थी कि हमें इस बात की बहुत खुशी है कि हमारे यहां जो इलैक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, वह बहुत अच्छा काम कर रहा है और सारी दुनिया में उसकी साख है।...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Please maintain order in the House.

श्री जय प्रकाश अग्रवाल : महोदया, सौ करोड़ के हिन्दुस्तान में चुनाव होते हैं, सरकारें बनती हैं और बहुत शांति से, सिवाए कुछ हादसे होते हों जो शायद एक प्रतिशत भी नहीं होते और हमारे लोगों को बुलाकर बाहर एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए बात की जाती है कि किस तरह से हम चुनाव कराते हैं और किस तरह से शांति से चुनाव होते हैं। लेकिन मेरा मंत्री जी से एक बात कहना बहुत जरूरी है और वह यह है कि आपने चुनाव के दौरान साप्रदायिकता के बारे में बात कही है कि हम साप्रदायिक नारा नहीं दे सकते, हम भगवान का नाम नहीं ले सकते या हम कोई भी धार्मिक मुद्दा उठाकर चुनाव नहीं लड़ सकते। लेकिन उसमें मेरा यह मानना है कि बहुत सारे हादसे चुनाव से पहले चुनाव के लिए होते हैं। चुनाव के दौरान भी कई बार वे बातें कही जाती हैं।

MADAM SPEAKER: Please maintain order, hon. Minister, hon. Members.

श्री जय प्रकाश अग्रवाल : अध्यक्ष महोदया, लगता है कि वह बहुत गहरी चिंता में है। जिस समय हम चुनाव लड़ते हैं, उस समय कहा जाता है कि धार्मिक मुद्दा नहीं उठाया जाएगा, उस समय भी वे मुद्दे उठाये जाते हैं लेकिन उसका कोई संज्ञान नहीं लिया जाता।...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: I would like to tell all the hon. Members and I have said it earlier also that when one hon. Member is speaking, please do not cross the floor. It is against Parliamentary decorum and it is not courteous to the Member who is speaking. Please observe that in future.

श्री जय प्रकाश अग्रवाल : अभी हमने देखा जैसे महाराष्ट्र में हुआ, एक पोलिटिकल पार्टी है और उन्होंने वहां पर कुछ हादसे करे जिसकी वजह से वहां जो माइनॉरिटी में लोग रहते हैं या उस राज्य में जाकर जो लोग रहते हैं, उनको डराने की कोशिश की गई, उनको धमकाने की कोशिश की गई और उनको मारा गया। ये सारी चीजें चुनाव से पहले हुई। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आप जब यहां कानून बना रहे हैं, तो कुछ ऐसे कानून भी बनाइए जिसके अंदर राजनैतिक पार्टियों के ऊपर जो वे सिद्धान्त लेकर चलते हैं, अगर वे सही नहीं है तो पाबंदी उसके ऊपर लगायी जानी चाहिए। यह नहीं हो सकता कि हम सिर्फ उस दायरे को उसी समय के लिए सीमित करें जब से चुनाव डिक्लेअर होते हैं और बाकी हम उनको खुला छोड़ दें। गुजरात में जो हुआ, आपने देखा यह चुनाव से पहले हुआ। वोट मांगने की राजनीति में एक वहशी रास्ता इस्तेमाल किया और वह रास्ता इस्तेमाल किया जो शायद लोकतंत्र के लिए काला धब्बा था। हम जिस तरह धार्मिक मुद्दा लेकर बात करते हैं और आप कहते हैं कि किसी भी चुनाव में धर्म का मुद्दा नहीं उठाया जाना चाहिए। यह बात सही भी है क्योंकि 100 करोड़ आबादी वाले देश में तरह-तरह के रहने वाले, तरह-तरह की पोशाक पहनने वाले और तरह-तरह की भाÂाा बोलने वाले लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और उनके ऊपर अत्याचार करके इस तरह से डराया या धमकाया जाएगा तो यह किसी भी लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। हम कोई अच्छी मिसाल कायम नहीं कर रहे हैं। आप धर्म की बात कहते हैं तो मैं जानना चाहता हूं कि धर्म के नाम से कोई भी राजनीतिक पार्टी कैसे रजिस्टर्ड हो जाती है? क्या आप इस संबंध में कोई कानून बनाने वाले हैं? आप कहते हैं राम का नाम मत लो लेकिन आपने देखा किस तरह रथ यात्रा निकली और किस तरह से भगवान का नाम लेकर पूरे चुनाव को एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश की गई। शिव सेना एक राजनीतिक पार्टी है और जब आप इतनी पाबंदियां लगाते हैं तो क्या शिव के नाम से राजनीतिक पार्टी का नाम रखा जा सकता है? क्या भगवान के नाम से किसी राजनीतिक पार्टी का रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है? मुझे इसके दोनों शब्दों पर एतराज़ है - एक, भगवान के नाम से लिया गया यह शब्द और दूसरा, सेना। आज सेना के नाम से लोग सैनिक बल को सलाम करते हैं।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आपका कौन सा नियम है? नियम बताइए। There is no point of order. Please take your seat.

श्री जय प्रकाश अग्रवाल : महोदया, मैं चाहता हूं कि अगर कोई बहस चाहे तो आप इस पर बहस करें। मेरा मानना है कि जब धर्म की पाबंदी चुनाव में है, वह होनी चाहिए लेकिन इस तरह की राजनीतिक पार्टी के नामों का रजिस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए। उनको इस तरह से काम करने की छूट नहीं दी जानी चाहिए। आपने इलैक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मार्फत कुछ कानून बनाए। राजनीतिक पार्टियों का नाम बैलेट और मशीनों में ऊपर आता है। मध्य प्रदेश में अभी चुनाव हुआ और मैंने देखा, अखबार में देखा कि इसमें राजनीतिक दल के उम्मीदवार का नॉमिनेशन रिटर्निंग अफसर पर दबाव देकर कैंसल कराया गया। वह उम्मीदवार श्रीमती सुÂामा स्वराज के मुकाबले खड़ा था। आपका कोई दबाव किसी दूसरी स्टेट पर नहीं है। मेरा मानना है कि उम्मीदवार चाहे किसी राजनीतिक पार्टी का है, कांग्रेस, बीजेपी, कम्युनिस्ट पार्टी या किसी और पार्टी का है और बहुत ही छोटे ग्राउंड पर जबरदस्ती दबाव दिया जाता है तो क्या आप कानून द्वारा प्रोटेक्शन देंगे कि आइंदा किसी और स्टेट में किसी भी राजनीतिक पार्टी के उम्मीदवार के साथ ऐसा न हो। कांग्रेस के उम्मीदवार का नॉमिनेशन जबरदस्ती कैंसल कराया गया और उसे चुनाव से बाहर कर दिया गया। क्या आप इस संबंध में कानून बनाकर सख्ती दिखाएंगे?

महोदया, जब हम इस हाउस से बाहर जाते हैं तो हम प्रेस के फ्रीडम की बात कहते हैं। उस दिन मैंने देखा, जितने सदस्य इस हाउस में बोले, उनमें से एक भी व्यक्ति ने प्रेस के फ्रीडम की बात नहीं कही। क्या यह माना जाए कि अगर प्रेस कुछ लिख देता है तो सारे लोग उसी तरफ वोट दे देते हैं। अभी कितने एक्जिट पोल हुए और सारे फेल हुए। मुझे नहीं लगता शायद दो, चार या पांच परसेंट कह दें, उसमें भी दस परसेंट ज्यादा या कम करके टीवी में कहते हैं कि एक्जिट पोल है इसलिए दस प्लस या माइनस होगा। आज हिरेन पाठक यहां नहीं बैठे हैं, उन्होंने बड़ा जोरदार भाÂाण दिया था कि प्रेस पर पाबंदी लगनी चाहिए, प्रेस को अलाऊ नहीं करना चाहिए और यह बिल में भी कहा गया। लेकिन वे बाहर जाकर प्रेस फ्रीडम की बात कहते हैं। यह दोगली बात है, अंदर कुछ कहना और बाहर कुछ कहना। मुझे लगता

है यह सही नहीं है। आप कानून बना रहे हैं, मैं सौ फीसदी सहमत हूं। मैं आज भी कहता हूं कि प्रेस्टीज इन्वाल्वड होती है, प्रतिÂठा का प्रश्न होता है। मान लीजिए टीवी पर एक्जिट पोल आता है और वह सही नहीं होता तो लोग कहते हैं कि यह चैनल सही नहीं है, ये इसी तरह का काम करते हैं। यह इनका काम है, यह रोज एग्जिट पोल दिखाते हैं और गलतबयानी करते हैं। मेरा मानना यह है कि हमें खुली छूट देनी चाहिए और हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि वे लोकतंत्र के किसी मजबूत पाये को नुकसान न पहुंचा सकें। लेकिन यदि प्रैस पर आप पाबंदी लगायेंगे तो शायद यह शुरूआत आज यहां से होगी और फिर कहीं और जायेगी। इसलिए जो मेरा मानना है वह शायद सही नहीं है।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं। मैंने अपना प्राइवेट मैम्बर बिल भी पेश किया है और उस पर मैं बोलूंगा। उसमें मैंने कहा है कि वोटिंग कम्पलसरी होनी चाहिए। यदि आज आप देखें, हम यह कहकर बड़े खुश होते हैं कि हमारे यहां पचास परसैन्ट पोलिंग हो गई, पचपन परसैन्ट या साठ परसैन्ट पोलिंग हो गई। लेकिन हम कभी इसका दूसरा पहलू नहीं देखते। इसकी क्या वजह है। चालीस परसैन्ट कम आबादी नहीं होती। क्या चालीस परसैन्ट लोग हमारे लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते? क्या चालीस परसैन्ट लोग हमारी कार्य प्रणाली में विश्वास नहीं रखते? क्या चालीस परसैन्ट लोग यह समझते हैं कि जो चुनाव हो रहे हैं ये देश के हित में नहीं है या ये लोग वहां बैठकर हमारे हित में काम नहीं करेंगे। आज हमारा बढ़ता हुआ हिंदुस्तान है। दुनिया देख रही है कि हम क्या करते हैं। दुनिया देख रही है कि हम किस तरह से फैसले करते हैं। दुनिया हमें आगे बढ़ते हुए देख रही है। लेकिन हमारा जो यह बढ़ता हुआ कदम है, इसमें क्या वजह है कि चालीस परसैन्ट लोग हमारे साथ नहीं है। इसलिए मंत्री जी मेरा मानना है और मैं आशा करता हूं कि आप जो जवाब मेरे प्राइवेट मैम्बर बिल पर देंगे, वह अलग है, लेकिन मेरा मानना है कि जब आप जवाब दें तो इस पर भी जरूर रोशनी डालें।

आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं। अभी कुछ दिन पहले हमारे चीफ इलैक्शन कमिश्नर के खिलाफ बहुत सारी बातें कही गई, बहुत सारी मुहिम यहां चलाई गई। मेरा मानना यह है कि किसी भी इंस्टीट्यूशन को छोटा करके हम बड़े नहीं हो सकते। हमारे कई हिस्से हैं - ज्यूडिशियरी है, इलैक्शन कमीशन है, एक्जीक्यूटिव विंग है, इलैक्ट्रिकल विंग है। मेरा मानना यह है कि हमें एक हद में रहकर प्रोटैस्ट करना चाहिए। लेकिन पूरे इंस्टीट्यूशन को, किसी एक व्यक्ति की जाति तौर पर शायद हमें उसकी शक्ल पसंद न हो। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम सारे कायदे-कानून तोड़कर दुनिया में यह दिखाने की कोशिश करें कि हमारा वह विंग अच्छा नहीं है या Election Commission of India is not headed by a descent man or a competent man. मैं आशा करता हूं कि मंत्री जी जब आप जवाब देंगे तो मेरे इन मुद्दों का ध्यान रखेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री शरीफुद्दीन शारिक (बारामुला): ऑनरेबल स्पीकर, मुल्क में चुनाव से संबंधित जो यहां अमैंडमैन्ट रखा गया है, इस पर मैं मुक्तसर बात करना चाहूंगा। चूंकि हमारे संविधान ने, हमारे आईन ने, हमारे कांस्टीट्यूशन ने मुल्क को एक जम्हूरी मुल्क करार दिया है और इस जम्हूरियत के साथ हमारा हाल भी, हमारा मुस्तकबिल भी ताल्लुक रखता है। जितनी-जितनी जम्हूरियत मजबूत होती चली जायेगी, उतना-उतना हिंदुस्तान में यगानहत होगी, प्यार-मौहब्बत बढ़ती जायेगी, मुखालफतें कम होंगी, दूरियां मिट जायेंगी, मौहब्बतें बढ़ेंगी और हम आपस में साथ-साथ मिल करके चलेंगे। जाति-पाति, भेदभाव मिट जायेगा। जितना ज्यादा स्ट्रिक्टली नेकनीति से जम्हूरियत पर अमल किया जायेगा।

मरहूम जुल्फिकार अली भुट्टो से पूछा गया था कि हिंदुस्तान के इतने मसाइल हैं, इतनी रियासतें हैं, इतने बोल हैं, इतने जबानें हैं, इतने लोग हैं, इतने कल्चर हैं, फिर ये लोग कैसे इकट्ठे हैं। उन्होंने कहा था कि ये इसलिए इकट्ठे हैं कि वहां जम्हूरियत है, हर एक को अपनी बात रखने का, अपनी शिकायत रखने का पूरा अधिकार और पूरा इख्तियार है। इस तरीकेकार को मजबूत करना हर हिंदुस्तानी का फर्ज है। लेकिन देखा गया है, मुझे इस सदन में कोई बताये क्या किसी अम्बानी का, किसी टाटा का, किसी बिरला का बेटा या खुद पिछले पचास सालों में उन्हें कहीं लाइन में वोट देते हुए देखा गया है। यदि वोट डालते हुए देखा गया है तो गरीब-गुरबा को वोट डालते हुए देखा गया है। गरीब-गुरबा लोग हमेशा वोट डालने आये हैं। क्या ऐसा कोई तरीका नहीं हो सकता है कि आप कम्पलसरी वोटिंग के लिए कानून में तरमीम कर लें। क्यों कोई लोग गरीब वोट डालते जाएं और अमीर लोगों को उसका फायदा मिलता रहे। उनको शर्म आयेगी कि हम लाइन में बैठे हैं और पोलिंग बूथ पर जाकर वोट डालने से वे कतरायें। इस चीज को हुकूमत को देखने की जरूरत है और ज्यादा फायदा फिर उन्हीं लोगों को पहुंचता है, जो लोग जम्हूरियत को मजबूत करने के लिए आगे नहीं आते।

दूसरी बात यह है कि जब अग्रवाल जी बताते हैं कि 40 परसेंट वोटिंग हुई, 50 परसेंट वोटिंग हुई तो हम सब लोग बगलें झांकते हैं। हम इस बात से इतराते हैं लेकिन हम यह नहीं समझते कि यह लोक सभा का मुकद्दस ऐवान, आपका हाउस, सारे हन्दुस्तान की नुमाइंदगी का दावा नहीं कर सकता क्यों कि यहां सिर्फ 30 परसेंट, 40 परसेंट या 50 परसेंट वोटर्स आये हैं। हम से पूछे कि क्या हम मुल्क की नुमाइंदगी करते हैं लेकिन हमारे आदाद व शुमार, हमारे आंकड़ें बता रहे हैं कि हम सारे मुल्क की नुमाइंदगी नहीं कर रहे हैं। मुल्क का बहुत सारा हिस्सा 50 परसेंट, 50 करोड़ लोग इस ऐवान से बाहर हैं, उनकी नुमाइंदगी नहीं हो रही है। इसको हमारे दानिशवरों को, हमारे कानूनदानों को जम्हूरियत में यकीन रखने वालों को और सारी पार्टियों के रहनुमां हैं, उनको सिर जोड़कर बैठना चाहिये, जम्हूरियत में यकीन रखने वालों को इस चीज पर गौर करना चाहिये। इसी तरह जम्हूरियात के लिये जिन्दगी है। इंतखाबात साफ-सुथरा और जब तक गैर-जानिबदार न होगा, वह इंतखाबात नहीं हो सकता है।

मैडम स्पीकर, आप किसी प्रदेश में जाइये, बिहार में जाइये या दूसरी जगहों पर जाइये, बन्दूक के सहारे वोट डलवाये जायें और गुंडे मशीनें और पोलिंग बॉक्स उखाड़कर भाग जायें और हम उनपर काबू न पा सकें। जब इलैक्शन होता है तो लगता है कि इस मुल्क की उन रियासतों में भूचाल आयेगा। गुंडों को पैसा का लालच आता है, उन्हें पैसे दिये जाते हैं, उन्हें मैन पॉवर दिया जाता है, गुंडे लाये जाते हैं। हम इसे गैर-जानिबदार इलैक्शन नहीं कह सकते जब तक लॉ एंड ऑर्डर का आम आदमी को दिल में खौफ नहीं होना चाहिये, और वोट का इस्तेमाल करना चाहिये। उसके बाद माली इखराज़ात जो हमारे पास इस वक्त हैं, वे बहुत कम हैं, उन्हें बढ़ाने की जरूरत है। मैंने इलैक्शन लड़ा है और जब काउंटिंग के वक्त मैं 40 हजार वोटों से आगे चल रहा था तो एन.डी.टी.वी पर मेरे मुखालिफ के बारे आ रहा था कि वह 700 वोटों से लीड कर रहा है। इससे शक पड़ता है कि शायद प्रैस में भी कई लोग ऐसे हैं जो गलतफहमी पैदा करते हैं जिसे मैं ठीक तरह से समझा नहीं। मैं इस सिलसिले में यह गुजारिश करूंगा कि जो बदकिरदार लोग हैं, वे किसी भी हालत में इलैक्शन में नहीं आयें। पैसे के जोर से असर के जोर से,, गुंडागर्दी के जोर

से ऐसे लोग कामयाब होने की कोशिश करते हैं जो समाज में बदनाम हैं जिन्होंने समाज का गला घोंटकर रखा है, वह आदमी भी यहां आने की कोशिश कर रहा है। इस कानून को देखने की जरूरत है।

मैडम स्पीकर, एक नाम दहशतगर्दी का लश्कर-ए-तैय्यबा है जिसे आप सुनकर हैरान हो जायेंगी। हर एक शख्स जानता है कि कितना पाकिजा नाम है जिसका मतलब है कि पाक लोगों की सेना, पवित्र लोगों की सेना है लेकिन काम क्या देखते हैं? इसी तरह शिव सेना का नाम है, फिर लश्कर-ए-तैय्यबा में क्या फर्क है? इन बातों को देखना पड़ेगा, कानून में अमेंडमेंट करना पड़ेगा। साफ-सुथरी जम्हूरियत के लिये हिन्दुस्तान पैदा हुआ है । ऐसी जम्हूरियत के लिये, जहां कोई भेद-भाव न हो,जहां कोई दखल न हो, जहां कोई गुंडागर्दी न हो, इसी के साथ मैं इस तरमीम की हिमायत करता हूं।

डॉ. तरुण मंडल (जयनगर): अध्यक्ष महोदया, जो इंडेपेंडेंट और छोटी पार्टी का सदस्य होता है, इस संबंध में हमारे मंत्री महोदय इलैक्शन के समय उसकी जमानत, सिक्यूरिटी डिपॉज़िट की राशि बढ़ाने का जो फैसला लिया है, मैं उससे बिलकुल सहमत नहीं हूं। यह गलत है क्योंकि हमारा जो मौलिक अधिकार है, हमारे देश का एक अमीर और एक गरीब पैसे के कारण चुनाव में खड़ा नहीं हो सकेगा , यह कभी नहीं हो सकता है To vote and to be voted, and to elect and to be elected is a fundamental right of our citizens. इसको रोकना नहीं चाहिये और आजकल निर्वाचन सदन से जो कानून लागू कर रहा है, हमारे चुनाव लड़ने के टाइम हमारे प्रचार करने के ऊपर यह देखा जाता है कि आजकल दीवारों पर पोस्टर लगाना या दीवार पर लिखना जो हमारे कनवैंशनल मैथड था,

13.00 hrs.

जो छोटी पार्टी और निर्दलीय प्रत्याशी उसको इस्तेमाल करते थे, उन्हें वह रूकावट लगा देता है। आज इलेक्ट्रानिक मीडिया में जाओ, प्रिंट मीडिया में जाओ तो वहां बहुत पैसा खर्च करने की बात होती है। कोई बड़ी पार्टी होती हैं, जैसे आई.एन.सी. है, बीजेपी है, सीपीएम जैसी पार्टियों के पास बहुत पैसा है, मैंने पेपर में देखा है कि ये बहुत धनवान हैं। यह सुविधा उन लोगों के लिए हो सकती है, लेकिन हम लोगों की छोटी पार्टी के लिए यह सुविधा नहीं होगी।

महोदया, मेरी तीसरी बात है, आज जो यह आवाज उठ रही है कि सभी के लिए वोट कंप्लसरी करना चाहिए, मैं इसके भी विरोध में हूं। यह एक फांसीवाद की आवाज है, स्टेट की ओर से कहा जाता है कि एक फंडामेंटल राइट जनता का रहता है कि मैं वोट दूंगा या नहीं दूंगा। हम लोगो को इसके बारे में सोचना चाहिए कि 62 साल के बाद हमारे जनतंत्र में क्यों आदमी हम लोगों को वोट देने के लिए नहीं आ रहा है? किसे वोट डालें, वह इनकॉफीडेंस है? इसे हमें देखना चाहिए। इंटरनेट खोलकर देखिए, आज दुनिया के सभी बड़े-बड़े जनतंत्र में जर्मन में, इंग्लैंड में देखा जाए तो वोट 70-80 फीसदी से कम होकर 50-55 से 60 फीसदी में आ रहा है। यह हमारे भारत के लिए कोई नयी चीज नहीं है। आम जनता और हमारे मेंबर्स लोगों को सोचना चाहिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं, जो हमें आम जनता वोट देने के लिए नहीं आ रही है।

महोदया, एक बात और है कि बड़े-बड़े कॉरपोरेट हाउस से, इंडस्ट्रियलिस्ट्स के पास से पैसा लेने का जो फैसला इससे पहले किया है, यह गलत है। कोई पार्टी जब इनसे पैसा लेती है तो वह उनके लिए ही काम करेगी, वह आम जनता के लिए काम नहीं करेगी और हर चुनाव के बाद मंहगाई बढ़ेगी। एग्जिट पोल, और ओपीनियन पोल, बंद होना चाहिए। Media has its own class character and helps only bigger party candidates.

श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम (जामनगर): महोदया, मंत्री जी जो बिल लेकर आये हैं, उसका मैं सपोर्ट करता हूं और आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। इस बिल के बारे में बहुत चर्चा हो गयी है, लेकिन कुछ कमियां, जो इस बिल के बाद जो कानून आना चाहिए, उसमें जो हैं, उन पर मैं आपका और मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। खासकर हम चुनाव आयुक्त को जो पावर देते हैं, चुनाव आयुक्त उस पावर का इस्तेमाल करते हैं, उस पावर का इस्तेमाल करते-करते वह जो गलतियां करते हैं, उसके बारे में कहने वाला कोई नहीं है। मैं गुजरात से आता हूं, मैं किसी पर ब्लेम नहीं करता, लेकिन एक पॉलिसी है, हर गांव से जानबूझकर कौन सी पार्टी को वोट देने वाला मेंबर है, 15-20 नाम कम कर दिये जाते हैं। जो लोग 50 साल से एक ही जगह पर रहते हैं, हर बार वोट करते हैं, जिसकी पैदाइश ही उसी जगह पर है, उसका नाम लिस्ट से क्यों गायब हो जाता है? इसकी जिम्मेदारी किसकी है? वह जिम्मेदारी चुनाव आयुक्त पर फिक्स होनी चाहिए। अगर वे गलती करते हैं, तो उनके लिए दंड का प्रावधान होना चाहिए।

महोदया, मेरी दूसरी बात है, हम लोग सब चुनाव लड़कर और जीतकर यहां बैठे हैं। हर सदस्य को यह मालूम है कि हमारे हजारों बैनर हर जगह पर लगे होते हैं। किसी ने रात को 2 बजे कोई एक बैनर उठाकर सरकारी इमारत पर लगा दिया तो हम गुनहगार बन जाते हैं। मैंने वर्ष 1998 में एक चुनाव लड़ा, मुझ पर आचार संहिता का केस कर दिया। मुझे इलेक्शन से तीन दिन पहले सुबह से शाम तक कोर्ट में बिठाकर रखा गया। 8 साल तक मेरा यह मुकद्मा चला, मैं एमएलए बन गया। मैं वर्ष 2004 में एमपी बन गया और मैं फिर से एमपी बन गया हूं, लेकिन 8 साल तक मेरा यह मुकद्मा खत्म नहीं हुआ। क्या मेरा इतना बड़ा गुनाह था, क्या वह गुनाह मैंने किया था? इस तरह की जो क्षतियां हैं, उन्हें चुनाव आयुक्त को देखना चाहिए। हजारों बैनर हर प्रत्याशी के अपने इलाकों में होते हैं और अपोजिशन वाले कोई भी एक बैनर उठाकर सरकारी इमारत पर लगा दें तो क्या हम गुनहगार बन जाते हैं?

महोदया, मेरा तीसरा प्वाइंट है कि हम लोग आईकार्ड दिखाकर वोटिंग कराते हैं, आईकार्ड तो पूरा है नहीं, उसके बाद हम ड्राइविंग लाइसेंस देखते हैं, पैन कार्ड देखते हैं। क्या गरीबों के पास ये सब चीजें हैं? हमारे यहां कुछ जातियां परमानेंट किसी पार्टी को वोट देती हैं। 24 घंटे पहले उसका आईकार्ड खरीद लिया जाता है।

वह आई. कार्ड कुछ पैसों में कुछ बिचौलिए खरीदते हैं ताकि वोटर वोट करने न जाए और शाम को जब उसका हाथ देखते हैं, उसने टिक नहीं किया तो उसका आई. कार्ड वापस हो जाता है। उसको पेमंट किया जाता है। इसलिए किसी एक चीज पर वोटिंग के लिए डिपेंड नहीं होना चाहिए। वोटर के पास कम से कम दस चीजें ऐसी होनी चाहिए ताकि कोई लोग आई. कार्ड, परमिट, लाइसेंस या कोई दूसरी चीज पैसे से न ले सके और वोटर निष्पक्ष चुनाव कर सके।

अध्यक्ष महोदया, मेरे पास इस पर बोलने के लिए तो बहुत कुछ है और इस पर सभी माननीय सदस्य बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन मुझे टाइम लिमिट मालूम है, इसलिए मैं एक प्वाइंट और बोल कर अपनी बात समाप्त करूंगा। प्रेस मीडिया की जो भूमिका है, मैं यादव हूं और मैं इलैक्शन लड़ता हूं, हर कोई अपनी-अपनी जाति से है। अगर किसी एक राजपूत और एक यादव के लड़के ने झगड़ा कर लिया तो प्रेस के अंदर आता है कि यादव और राजपूतों में बड़ी लड़ाई हो गई, क्या कोई जातियां लड़ती हैं? किसी भी जाति के दो व्यक्ति लड़ते हैं, माइनोरिटी और दलित, ट्राइबल और ब्राह्मण भी लड़ते हैं। प्रेस पर यह कंट्रोल होना चाहिए और खास कर इलैक्शन टाइम पर किसी भी जाति को भड़काने का काम नहीं होना चाहिए। जो भी आदमी लड़ता है, उसका नाम बताया जाए, क्योंकि कभी-कभी कोई जातियां आपस में लड़ती ही नहीं हैं। दो आदमियों का झगड़ा होता है, इतनी बड़ी डिस्ट्रिक्ट होती है और इतने बड़े वोटर्स होते हैं, इनमें वोट की लड़ाई भी नहीं होती है, अपनी-अपनी लड़ाई होती है।

अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे इस बिल पर बोलने का मौका दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

THE MINISTER OF LAW AND JUSTICE (SHRI M. VEERAPPA MOILY): Madam Speaker, I am thankful to all the hon. Members who have participated in an important debate particularly on the amendments which have been introduced to the Representation of the People Act.

During the introduction of the Bill, I had said that the Election Commission had forwarded 22 recommendations. In fact, all of them have been forwarded to the Departmentally-related Standing Committee. The Standing Committee recommended in respect of five components of these 22 recommendations and 17 recommendations are still pending with the Standing Committee from 2004. I am thankful that, by and large, the hon. Members have extended their support to this Bill. I have already said that this is not just enough. We are going to come out with a comprehensive amendment for the Representation of the People Act. We would like to discuss with the Members of Parliament, all the stakeholders maybe somewhere in June or July, I would like to have a National Consultation on a comprehensive amendment to the Representation of the People Act. It is necessary because after 60 years, many things have happened and many things will have to be given an answer, many of the distortions and challenges which have been posed in the process of election needs to be answered.

Shri Nishikant Dubey mainly raised a point with regard to the person who is in jail and who is deprived of contesting election or casting his vote. Sub-section (v) of Section 62 of the Representation of the People Act provides that no person shall vote at any election if he is confined in a prison whether under a sentence of imprisonment or transportation or otherwise or is in the lawful custody of the police.

This shall not apply to a person subject to preventive detention. These provisions have been there for fifty years. I think we need to address these problems. I can understand it in case of a person who is sentenced. But even a person who is lodged in lawful custody of police is also deprived of voting. I think this is a matter which needs to be addressed. Maybe we can consider this issue when we bring forth a comprehensive amendment Bill.

Shri Dubey raised a point with regard to negative voting. This point has been discussed by the National Commission to Review the Working of the Constitution. The Commission opined that it will not serve any purpose. Since there is no system of compulsory voting, a voter being at liberty to exercise his franchise or not, there is no need to provide for negative voting. Unless we think of getting into a regime of compulsory voting, I do not think the concept of negative voting could be introduced.

Hon. Members Shri Nishikant Dubey and Shri Sandeep Dikshit have raised certain very important issues with regard to the media practices. This is a recent phenomenon and is a matter of concern. Much has been said in this regard and I do not want to say all that. They also raised the issue of surrogate advertisement. It is not direct advertisement but it is surrogate or virtual advertisement. They have said that there should be a ban on election advertisements, particularly beginning from a few months earlier to the elections. This is also an issue which needs greater deliberation.

They raised a question about one of the Election Commissioners. This is a matter which has already been considered carefully by the Government and the order has been communicated to the then Chief Election Commissioner. This issue does not survive for any more reflection or deliberation as of today.

Another question which was raised was about the Anti-Defection Law, though it is not pertinent to the amendments pending before the House. There is a recommendation of the Election Commission of India for empowering the President

and the Governor to act upon a recommendation made by the Election Commission on a question of anti-defection. This is a debatable point, a matter which needs to be properly deliberated upon.

On the issue with regard to the poll to be taken up on the same day throughout the country, Madam Speaker, it is an ideal thing, a Utopian idea to be considered. Given the practical knowledge of all the hon. Members of the House, is it possible? Of course, there were hon. Members who even went to the extent of saying that all elections – from Panchayat elections to elections to Assemblies and Lok Sabha – together. I can understand very well the question as to why we could not consider holding elections to Assemblies and the Lok Sabha together. It is not an easy a thing to do because varied dates have already been set for elections to these various bodies. Unless all political parties join together and say that there should be simultaneous elections to all the State Assemblies and the Lok Sabha, it is not possible. It is a major decision to be taken.

Mr. Sandeep Dikshit raised another particular question as to whether there was a case wherein a sitting MP had to be unseated due to corrupt practices. He said that there was none. But, there are some instances. Recently, the election of Shri P.C. Thomas had been set aside holding him guilty of indulging in corrupt practices by asking for votes in the name of a community or religion.

That was one case. Then in 1988, there was yet another case. The election of Dr. Ramesh Yashwant Prabhu was set aside on the grounds of corrupt practices. Further, in the same case, the court also named Shri Bal Thackeray under section 99, finding him guilty of corrupt practices along with the returned candidate and disqualified for a period of six years with effect from 11.12.1995.

I must bring it to the notice of the hon. House, the best example set by late Shri Jawaharlal Nehru. It happened in 1951 – it was not because of the election, but because of certain letter written by him. As on today, if you look back, it may look as if it is innocuous. Just because he recommended some person for some favour to the Ministry, he was asked to be unseated. Even though the Committee found that it was not a matter which should be taken up seriously, late Shri Jawaharlal Nehru stood up and said that that particular Member, Shri Mudgal will have to be unseated. This is the great tradition of this House; this is the great legacy. It was a small innocuous letter recommending that some favour may be done, written by a Member to a Minister; it was the highest ideal of democracy. I just wanted to bring it to the notice of the House. But now, I think, practically, every MLA and every MP, will have to be done like that, if we apply that rule. But I am telling you the laudable principles that were kept in this great House of democracy.

I do not think, I need to dwell much on the compulsory voting. Shri Shailendra Kumar raised this issue. In fact, this was an issue which was referred to by Dinesh Goswami Committee. It considered the proposal and it did not favour it. I can refer to only one sentence. It said:

> "Having regard to the social and literacy backwardness of considerable number of people in the country, and the fact that right to vote includes right not to vote in our democratic system, it is not practicable to accept the suggestion further due to lack of literacy, shelter and other amenities, and a lot of persons find it difficult even to get registered as voters. Hence, the time is not ripe for providing any law for compulsory voting."

This is what was referred to. ...(*Interruptions*)

SHRI JAI PRAKASH AGARWAL : When did this report come – in which year? ...(*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Please address the Chair.

...(*Interruptions*)

SHRI M. VEERAPPA MOILY: Definitely we can have a discussion on that. If we have to reconsider that recommendation, let us discuss about it. I do not say that I have a closed mind on that. ...(*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Please let him reply. I am sure, he will address all your concerns.

SHRI M. VEERAPPA MOILY: I do not have a closed mind. I have an open mind. If additional factors could be brought in, it is all right. The first thing is that it should be practical. Secondly, it should be seen whether it is conducive to the present atmosphere. These are the two factors to be considered; we do make an exercise.

Shri Rajiv Ranjan Singh has suggested that control on election expenses is possible, only when the candidates contest elections at the Government expenses. Shri Harin Pathak also said that check on muscle power along with money power in the election should be there, and that the entire election expenses should be funded by the Government. The

recommendations of the Indrajit Gupta Committee have been the basis of the present proposal and the subject is pending consideration of the Government. It is still under consideration. We have written to all the State Governments, but to be very frank with you, the response of the State Government is, to say the least, lukewarm.

It is because they need to incur the expenditure. If you all prevail upon the State Governments and make them agree maybe a worthwhile beginning can be made. The Election Commission also held a number of meetings with all the political parties on this issue. I do not say that nothing has happened. Some of these things have happened but major things have not happened. With regard to Shri Indrajit Gupta Committee's recommendation regarding setting up of a corpus for election fund of Rs.1200 crore with the States' contribution of Rs.600 crore annually to the fund, the States have been unwilling on this measure. The Cabinet in its meeting held on 17th May, 2007 directed that efforts be continued to make a consensus on this issue. We have not closed the issue but there should be a political consensus on it. The issue is still open.

I must here particularly draw the attention of the hon. Members to one statement of Dr. B.R. Ambedkar, which according to me is very relevant:

> "It has been brought to the notice of both the Drafting Committee and the Central Government that in these provinces the executive Government is instructing or managing things in such a manner that those people who do not belong to them either racially, culturally or linguistically are being excluded from being brought on the electoral rolls. (This has been happening.) The House will realise that franchise is the most fundamental thing in a democracy. No person who is entitled to be brought into the electoral rolls on the grounds which we have already mentioned in our Constitution namely; an adult of 21 years of age (Now it has been reduced to 18 years) should be excluded merely as a result of a prejudice of a local Government or the whim of an officer. That would cut at the very root of the democratic Government. In order, therefore to prevent injustice being done by provincial Government to people other than those who belong to the province racially, linguistically and culturally it is felt desirable to depart from the original proposal of having a separate Election Commission for each province under the guidance of the Governor and the local Government. Therefore, this new change has been brought about namely that the whole of the election machinery should be in the hands of a Central Election Commission which alone would be entitled to issue directives to Returning Officers, Polling Officers and others engaged in the preparation and revision of electoral rolls so that no injustice may be done to any citizen in India who under this Constitution is entitled to be brought on the electoral rolls. That alone is, if I may say so, a radical and fundamental departure from the existing provisions of the draft Constitution."

I have read it because of the importance of the Election Commission of India. It is a matter of fact that even then some of these distortions are taking place. It is because the Chief Electoral Officers of respective States belong to the cadre of the State Government. Maybe, this is an issue which all the hon. Members can deliberate tomorrow to make it more objective. More power is to be given but at the same time the absolute power corrupts absolutely. That is a caution which has been administered by many of the Members of this House. At the same time, more components of objectivity will have to be introduced in the functioning of the Election Commission and in the functioning of their representatives at various levels in the States.

I would like to say that the machinery of the Election Commission should not be independent. I would like to quote late Shri K. Munshi with regard to the Election Commission. He gave a caution which many of the Members have expressed. To corroborate that I would like to read it out:

> "A machinery so independent cannot allow to sit as a kind of super Government to decide which Government shall come into powerâ€¦. "

> There will be a great political danger if the Election Tribunal becomes such a political power in the country. Not only it should preserve its independence but it must retain impartiality. Therefore, the Election Commission must rem0061in to a large extent an ally of the Government. Not only that, it must, to a considerable extent, be a subsidiary to the Government, except in regard to the discharge of the function allotted to it by law."

They should have the autonomous power but at the same time, autonomous power or the independence without a dominant factor of accountability will lead to many other distortions which I do not want to respond or illustrate as on today. But this is a matter which we also discussed.

Shri Sandeep Dixit has also raised a point regarding introduction of biometric system for voting. Now this may avoid a lot of

questions with regard to rigging and fraud in the polling booth. I think it is a very good idea which has been thrown by the hon. Member and we will definitely consider it seriously.

With regard to the problems relating to the alleged faulty voter ID cards, the system of taking biometrics would be considered. However, one of the ways in which this problem is being addressed is to prepare electoral rolls with the photograph of elector. A pilot project was undertaken in Kerala and Haryana and results were encouraging. Thereafter, it was rolled out throughout the country in a phased manner. As on date, all the States and Union Territories, except, Assam, Jammu and Kashmir and Nagaland have photo electoral rolls.

Further, as one of the measures to tackle this problem, an instruction has been issued by the Election Commission that the EPIC number once issued will be valid throughout the elector's life even if his address changes. This is one of the suggestions which is given and this is an innovative idea in India which needs to be deliberated upon by all the parties. Biometrics is one of the best solutions which have been provided by an hon. Member and we will definitely consider it.

Dr. Raghuvansh Prasad Singh has mentioned regarding alleged scam in EVMs by the Election Commission. EVMs are purchased exclusively from the public sector companies like Bharat Electronics Limited and Electronic Corporation of India. Hence the apprehension of any irregularity seems to be without much basis. Also stringent checks and balances are applied before the use of every EVM. Allegations have been made from different quarters regarding vulnerability of EVMs but no one till today could prove it after due opportunity.

As far as EVM is concerned, I do not think we need any advice from the foreign countries. In the field of information technology, our country is the best and we have captured the IT work. So, I think we have this kind of technology available and any of our engineers who would like to challenge our EVM and prove otherwise, we are prepared to accept their challenge. So, instead of spreading certain rumours on a particular system which is a proven system, I think we need to be very responsible on this. Of course, the concern raised by Dr. Raghuvansh Prasadji is quite genuine and I do not say that it is not there. But it has been a proven thing that there is no fraud.

As regards rigging, booth capturing and other related things, the procedure has been laid down under the Representation of People Act to empower the Election Commissioner under given circumstances for adjournment of poll and countermanding of elections. The normal procedure in this regard is that the Election Commission acts upon the basis of the report of the Returning Officer.

I do not want to describe things but there are two issues which I feel we need to address. First issue is regarding rigging. I think instead of leaving it to the only option or the discretion of the observer or the Returning Officer, we are considering laying down the objective parameters so that there can be some sort of a process of auto-piloting while ordering the re-polling.

There should be objective criteria in regarding to ordering of re-poll and also for recounting; otherwise if a person wins by one vote recounting is not ordered. There are certain distortions which have crept in. This will satisfy the Member if some objective criteria are brought in with regard to both rigging and consequent ordering of re-poll and also recounting. This will help address these issues. We will definitely work on this.

Shri Sandip Dikshit had raised the question of setting up of Electoral Tribunals for speedy disposal of election related cases. In fact, the High Court which has constituted Election Tribunals are expected to dispose of such cases within six months but this is not happening...(*Interruptions*) In fact, it has never happened so far and in this case we need to address this question. In the process of our legal reforms which we already have initiatedâ€¦ (*Interruptions*)

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): Can we not make it mandatory by making an amendment to the law?...(*Interruptions*)

SHRI M. VEERAPPA MOILY: Let us work on this. Decision in respect of the election related cases comes either after the next elections are held or just before the next elections are to be held. The decision in respect of such cases would have to be within six months of the elections held. We need to work on this. If an amendment to this effect is necessary, we will not hesitate to bring an amendment to the existing Act to make it absolutely mandatory and maybe have for some time judges exclusively meant for this purpose. We can have judges dedicated for this to dispose of the cases within six months. This may be a part of the legal reforms process which I have already initiated...(*Interruptions*)

SHRI KALYAN BANERJEE : So, after decades we are going to have judicial reforms.

SHRI M. VEERAPPA MOILY: Shri Rajiv Ranjan Singh `Lalan' raised the question about the status of the voter identity cards. He wanted to know if any State has achieved 100 per cent target in this regard. The Election Commission had initiated this process and as per figures as on 07.10.2009, the States of Kerala, Meghalaya, Tripura and Puducherry have achieved 100 per cent coverage. These figures are subject to any objection being raised by the hon. Members. These are according to our records. The States of Andhra Pradesh, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, Madhya Pradesh, Mizoram, Rajasthan, Sikkim, Tamil Nadu, Uttarakhand and the Union Territories of Chandigarh and Lakshwadeep has achieved more than 90 per cent coverage. Some States have achieved around 99 per cent coverage. We will expedite the process in respect of other States.

Madam, I would like to give a clarification in regard to bringing an amendment to Section 123(vii) of the RP Act, 1951. This clarification has been sought by Shri Kalyan Banerjee. The amendment to this Section in the Act is about the word `Government' under Section 123 of the General Clauses Act 1897 includes Central and State Government. Persons working under the Universities and Public Sector companies have not been included. That is why, even though an amendment of the Act has been brought about but we did not make the consequential amendment for the punishment of those officers who definitely commit some error while discharging their duties. That is why the amendment was brought here and is before the House.

Sir, Shri T.K.S.Elangovan raised the question of ordinary residents. The point is that we should not mix this issue with the question of NRIs. This is only for work purpose that these people go to other countries. Ordinarily, they are residents of that place. But many a times their names do not find a place in the electoral rolls because of their present place of residence. We are bringing an amendment in this regard. We have already proposed the amendment. The Bill is ready. There are some confusions. I would like to talk to my colleague Shri Vayalar Ravi in this regard. He is having a lot of interest in the matter and I would also talk to some of our Members of Parliament from Kerala. We are bringing an amendment to Section 24 of the RP Act, 1950.

Madam, Shri Arjun Sethi had asked if there is a change of policy with a change of Minister. That is absolutely not correct. I do not know as to what is the perception of the hon. Member. The policy has been clearly spelt out in the SOR and the Bill had been signed by the then Law Minister, Shri H.R.Bhardwaj and I have not made any changes thereafter.

So, these are some of the points which I would like to highlight. I have already said that I will definitely have a larger national consultation bringing out radical reforms....(*Interruptions*)

SHRI JAI PRAKASH AGARWAL : I asked whether a political party can be formed in the name of God? You have not replied to that point. ...(*Interruptions*) क्या सेना के नाम से कोई पोलिटिकल पार्टी हो सकती है और क्या भगवान के नाम से कोई पोलिटिकल पार्टी हो सकती है, इन दोनों के बारे में बताइए?

SHRI M. VEERAPPA MOILY: This is a right question raised by the hon. Member. But readymade answer is not available to this point. That is why, I would like to call you for a larger discussion. We will discuss about it. Undue, extraneous influence from the electors, from whichever quarter it comes, has to be halted. I agree with you. If we apply that principle, then it includes caste, religion, money and muscle power, etc.

We are the largest parliamentary democracy in the world. We have the largest number of electorates like 80 crores. Our parliamentary democracy is a role model for the entire world. That is why, we need to strengthen it and that could be strengthened by removing all distortions, prejudices and ulterior motives. Ultimately, the representatives of the people who come and occupy ...(*Interruptions*) That is why, I said that we will have a larger discussion and whatever deficiencies felt by the hon. Member will be deliberated upon and totally addressed in the days to come, when we will introduce a comprehensive Bill.

With these words, I request through you, Madam, for the kind support of the House. This will be an encouragement to bring about radical comprehensive Bill in future.

MADAM SPEAKER: The question is:

> "That the Bill further to amend the Representation of the People Act, 1950 and the Representation of the People Act, 1951, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MADAM SPEAKER: The House will now take up clause by clause consideration of the Bill.

MADAM SPEAKER: The question is:

"That clauses 2 to 5 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clauses 2 to 5 were added to the Bill.

MADAM SPEAKER: Let us take up clause No. 6. Amendment No. 1, Adv. A. Sampath is not present.

The question is:

"That clause 6 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 6 was added to the Bill.

Clause 7 was added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Long Title were added to the Bill.

SHRI M. VEERAPPA MOILY: I beg to move:

"That the Bill be passed."

MADAM SPEAKER: The question is:

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.